

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 737]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2025 — भाद्र 28, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2025

क्र. 6261/डी. 138/21-अ/प्रारू./छ.ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-08-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 30 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
(क्रमांक 7 सन् 2017) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.
 (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :
 परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस विधेयक के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।
 (क) धारा 6, 01 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त समझी जायेगी।
 (ख) धारा 2 से धारा 5 और धारा 7 से धारा 15, ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में, (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन.
 (एक) खंड (61) में, शब्द एवं अंक "धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) प्रतिस्थापित किया जाए, जो 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी ;

(दो) खंड (69) में,—

(क) उपखंड (ग) में शब्द “ऐसे नगरपालिका” के पश्चात्, शब्द “निधि” अन्तःस्थापित किया जाये ;

(ख) उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “स्थानीय निधि” से अभिप्रेत है, किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि ;

(ख) “नगरपालिका निधि” से अभिप्रेत है, किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि ;

(तीन) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(116क) “विशिष्ट पहचान चिह्नांकन” से अभिप्रेत है, धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिन्ह या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है।”

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 3. | मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप किया जाए । | धारा 12 का संशोधन. |
| 4. | मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप किया जाए । | धारा 13 का संशोधन. |

5. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में,— धारा 17 का संशोधन.
- (एक) शब्द “संयंत्र और मशीनरी” के स्थान पर, शब्द “संयंत्र एवं मशीनरी” प्रतिस्थापित किया जाए और इन्हें 01 जुलाई 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा ;
- (दो) शब्द “स्पष्टीकरण” के पश्चात्, अंक “1” को संख्याकित किया जाए और स्पष्टीकरण-1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
- “2. खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, “संयंत्र या मशीनरी” के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा “संयंत्र और मशीनरी” के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा।”
6. मूल अधिनियम की धारा 20 में, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी,— धारा 20 का संशोधन.
- (एक) उपधारा (1) में, शब्द एवं अंक “धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक “इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) प्रतिस्थापित किया जाए ;
- (दो) उपधारा (2) में, शब्द एवं अंक “धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक “इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) प्रतिस्थापित किया जाए ;
7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 34 का संशोधन.

“परंतु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि,—

(एक) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(दो) अन्य मामलों में, ऐसी प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है।”

8. मूल अधिनियम की धारा 38 में,—

धारा 38 का संशोधन.

(एक) उपधारा (1) में शब्द “स्वतः जनित विवरण” के स्थान पर, शब्द “कोई विवरण” प्रतिस्थापित किया जाए ;

(दो) उपधारा (2) में,—

(क) शब्द “के अधीन स्वतः जनित विवरण” के स्थान पर, शब्द “में निर्दिष्ट विवरण” प्रतिस्थापित किया जाए ;

(ख) खंड (क) में, शब्द “तथा” का लोप किया जाए ;

(ग) खंड (ख) में, शब्द “धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण” के पश्चात् शब्द “भी सम्मिलित हैं” अन्तःस्थापित किया जाए ;

(घ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।”

9. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, शब्द “रीति में और ऐसे समय के भीतर” के स्थान पर, शब्द “रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए” प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 39 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा 107 का संशोधन.

“परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।”

11. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में, धारा 112 का
निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:- संशोधन.

“परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।”

12. मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:- धारा 122ख का
अंतःस्थापन.

“122ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।”

खोज और
अनुसरण
क्रियाविधि के
अनुपालन में
असफल होने
पर शास्ति.

13. मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:- धारा 148क का
अंतःस्थापन.

“148क. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, :-

(क) माल ;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है,

को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे,

कतिपय मामलों
के लिए खोज
और अनुसरण
क्रियाविधि,

विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,—

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी ;

(ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति,—

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएगा ;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा ;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा ;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा,

जैसी कि विहित किया जाए ।”

14. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में :—

अनुसूची 3 का
संशोधन.

(एक) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए और इसे 01 जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किया हुआ समझा जाए, अर्थात् :—

“(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भाण्डागार क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल का प्रदाय ;”

(दो) स्पष्टीकरण 2 में, “पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए” शब्दों और अंक के स्थान पर, “पैरा 8 के खंड (क) के

प्रयोजनों के लिए" शब्द, अंक और कोष्ठक 01 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे;

(तीन) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए और इसे 01 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाए, अर्थात् :-

"3:-पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक जोन" "मुक्त व्यापार भाण्डागार क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं।"

टीप- सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहित किया गया है, किंतु जो इस प्रकार संग्रहित नहीं किया गया होता, यदि धारा 14 सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती।"

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2025

क्र. 6261/डी. 138/21-अ/प्रारू./छ.ग./25. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 30 of 2025)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2025.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by The Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. (1)** This Act may be called The Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025. **Short title and commencement.**
- (2)** It shall come into force on such date as the State Government may, by notification from the date of publication of Official Gazette, appoint:
- Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision,-
- (a) Section 6 shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2025;
- (b) Section 2 to 5 and Section 7 to 15 shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017) (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2,-

**Amendment of
Section 2.**

- (i) in clause (61), for the words, brackets and figure “sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9”, the words, brackets and figures “sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9 of this Act or sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (No.13 of 2017)” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2025;

- (ii) in clause (69),-

(a) in sub-clause (c), after the words “management of a municipal”, the word “fund” shall be inserted;

(b) after sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely:-

‘Explanation- For the purposes of this sub-clause-

- (a) “local fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic

functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;

- (b) “municipal fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called.;

- (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:—

“(116A) “unique identification marking” means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of Section 148A and

includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable.”

3. Sub-section (4) of Section 12 of the Principal Act, shall be omitted.

Amendment of Section 12.

4. Sub-section (4) of Section 13 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 13.

5. Clause (d) of sub-section (5) of Section 17 of the Principal Act,—

Amendment of Section 17.

(i) for the words “plant or machinery”, the words “plant and machinery” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;

(ii) after the word “Explanation” the figure “1.” shall be numbered and after Explanation-1., the following Explanation shall be inserted, namely:—

“2. For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to “plant or machinery” shall be

construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to “plant and machinery.”

6. In Section 20 of the Principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025,–

**Amendment of
Section 20.**

- (i) in sub-section (1), for the words, brackets and figure “sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9”, the words, brackets and figures “sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9 of this Act or sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (No.13 of 2017)” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2), for the words, brackets and figure “sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9”, the words, brackets and figures “sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9 of this Act or sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (No.13 of 2017)” shall be substituted.

7. In sub-section (2) of Section 34 of the Principal Act, for the proviso, the

**Amendment of
Section 34.**

“(c) such other details as may be prescribed.”

- | | | |
|------------|--|-----------------------------------|
| 9. | In sub-section (1) of Section 39 of the Principal Act, for the words “and within such time”, the words “within such time, and subject to such conditions and restrictions” shall be substituted. | Amendment of Section 39. |
| 10. | In sub-section (6) of Section 107 of the Principal Act, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten percent of the said penalty has been paid by the appellant.” | Amendment of Section 107. |
| 11. | In sub-section (8) of Section 112 of the Principal Act, the following proviso shall be added, namely:-
“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten percent of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of Section 107 has been paid by the appellant.” | Amendment of Section 112. |
| 12. | After Section 122A of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely:- | Insertion of Section 122B. |

“122B.- Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 148A acts in contravention of the provisions of the said Section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten percent of the tax payable on such goods, whichever is higher.”

Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.

13. After Section 148 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

Insertion of Section 148A.

“148A.- (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,—

Track and trace mechanism for certain goods.

- (a) the goods;
- (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this Section shall apply.

(2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),—

- (a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and
 - (b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.
- (3) The persons referred to in sub-section(1), shall,—
 - (a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;
 - (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;
 - (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity,

duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

- (d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2),

as may be prescribed.”

14.

In Schedule III of the Principal Act,—

**Amendment of
Schedule III.**

- (i) after clause (a) of paragraph 8, the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area.”

- (ii) in Explanation 2, after the words “For the purposes of”, the words, brackets and letter “clause (a) of” shall be inserted and shall be

deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017.

- (iii) after Explanation-2., the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

“3. For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions “Special Economic Zone”, “Free Trade Warehousing Zone” and “Domestic Tariff Area” shall have the same meanings respectively as assigned to them in Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.

Note- No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had Section 14 been in force at all material times.”